राज्यों में से एक राज्य है, विश्व बैंक की स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्ट में परियोजना के मध्य प्रदेश घटक के लिए 139.9 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, समग्र परियोजना के लिए 31-10-94 तक 14.850 मिलियन डालर की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(3) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना में भाग लेने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जिसके लिए ऋण दिए जाने की अंतिम तारीख 31-3-1995 है। समग्र परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 127.270 मिलियन डालर की राशि उपलब्ध कराई है। इसके विपरीत, 31-10-94 तक 118.321 मिलियन डालर की राशि का उपभोग कर लिया गया है।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आवंटन

829. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना (1994-95) परिव्यय की कितनी धनराशि की मांग की गई है और इस संबंध में जिलावार कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक तथा कृषि की क्या विकास दर निर्धारित की गई है ;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने सौराष्ट्र क्षेत्र के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के विकास में और तेजी लाने के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग राज्य के लिए एक साथ वार्षिक योजना परिव्यय स्वीकृत करता है, क्षेत्रवार अथवा जिलावार नहीं। 1994-95 में गुजरात के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय 2240 करोड़ रुपए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Central assistance to states

830. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the criteria for grant of Central assistance to States;

(b) the Central assistance provided to States during each of the last three years. State-wise and Union Territory-wise;

(c) the per capita central assistance provided to States during each of the last three years. State-wise and Union Territory-wise;

(d) resources mobilized by the States during each of the last three years. State-wise and Union Territory-wise; and

(e) the steps teken/proposed to be taken to bring parity in per capita Central assistance provided to States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The allocations of Central assistance to the States from 1992-93 to 1994-95 were made according to the formula as approved by the National Development Council in December, 1991. Details of the formula and criteria are given in Statement-I (*See* below).